बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्र010/विविध/वि0का0– 18/2015 - 326 खाद्य, पटना/दिनांक– 19.1.2018

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग/कृषि विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग/सहकारिता विभाग/शिक्षा विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 अंतर्गत अधिप्राप्ति किये गये धान/चावल की गड़बड़ी एवं गबन/क्षति करने वाले क्रय केन्द्र प्रभारी/कर्मियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने तथा संचालित विभागीय कार्यवाही में कृत कार्रवाई की अद्यतन सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 2908 दिनांक 09.04.2015, ज्ञापांक 3152 दिनांक 16.04.2015, पत्रांक 3147 दिनांक 16.04.2015, पत्रांक 4629 दिनांक 11.06.2015, पत्रांक 8923 दिनांक 25.11.2015, पत्रांक 519 दिनांक 25.01.2016, पत्रांक 3612 दिनांक 10.06.2016, पत्रांक 6028 दिनांक 06.10.2016, पत्रांक 1715 दिनांक 06.04.2017, बैठक की कार्यवाही दिनांक 14.07.2017 का ज्ञापांक 3711 दिनांक 31.07.2017, पत्रांक 3793 दिनांक 04.08.2017 एवं पत्रांक 4586 दिनांक 13.09.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध विभिन्न विभागों के स्तर पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में दिनांक 14.07.2017 को सम्पन्न बैठक में अवगत कराया गया था कि खरीफ विपणन मौसम, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 अंतर्गत दोषी प्रमादी मिलरों एवं कर्मियों के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2017 को पारित आदेश के आलोक में एस0आई0टी0 का गठन किया गया है। ऐसी स्थिति में विभिन्न विभागों के स्तर पर दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध की जा रही अनुशासनिक कार्रवाई पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

विदित हो कि बैठक के दौरान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अनुरोध किये जाने तथा लगातार स्मारित किये जाने के पश्चात भी संबंधित विभागों से प्राप्त चिन्हित दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई किये जाने से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र के अनुसार अद्यतन सूचना संकलित किये जाने में कठिनाई हो रही है।

अतः अनुरोध है कि मुख्य सचिव के स्तर से निर्गत पत्र सं0 7811 दिनांक 28.09.2015 द्वारा प्रेषित विहित प्रपत्र (छायाप्रति संलग्न) में चिन्हित दोषी कर्मियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए समेकित सूचना विहित प्रपत्र के साथ विभाग के नोडल पदाधिकारी को दिनांक 25.01.2018 को 12.30 बजे अप0 से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में भाग लेने का निदेश देने की कृपा की जाय।

अनु0 – यथोक्त।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

19/1/2018

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010/विविध/वि0का0– 18/2015 - 326 खाद्य, पटना/दिनांक– 19.1.2018

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि संबंधित विभागों से संबंधित जिला स्तर पर लंबित मामलों की सम्यक समीक्षा करते हुए जिला स्तर पर लंबित प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर नियंत्री विभाग को शीघ्र हस्तगत करायी जाय, साथ ही विभागीय कार्यवाही से संबंधित अन्य मामले यदि जिला स्तर पर लंबित है, तो समीक्षोपरांत उन मामलों को भी त्वरित निष्पादन करते हुए वांछित सूचना शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

19/1/2018

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010/विविध/वि0का0– 18/2015 326 खाद्य, पटना/दिनांक– 19.1.18

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

19/1/2018

सरकार के सचिव।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रमादी मिलर / गबन / अनियमितता के दोषी पदाधिकारियों / कर्मियों के विरूद्ध निलंबन / विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित प्रतिवेदन

विभाग / कार्यालय का नाम :– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना

क्र0 सं0	विभाग / निगम / प्राधिकार का नाम	चिन्हित पदाधिकारियों की संख्या	जिला पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रपत्र 'क' की संख्या	01.04.15 को लंबित विभागीय कार्यवाही (प्रपत्र 'क') की संख्या	01.04.15 से प्रतिवेदित माह तक प्रारंभ किये गये विभागीय कार्यवाही की सं0	कुल लंबित विभागीय कार्यवाही की सं0	निलंबित पदाधिकारियों / कर्मियों की संख्या	वादों की संख्या जिसमें संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है	वादों की संख्या जिसमें अंतिम आदेश पारित किया गया	अंतिम आदेश हेतु लंबित वादों की संख्या	जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण लंबित वादों की संख्या			जांच प्रतिवेदन के लंबित रहने के कारण		न्यायालय में विभागीय कार्यवाही से संबंधित लंबित मामलों की संख्या
											एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित वादों की संख्या	छः माह से अधिक अवधि से लंबित वादों की संख्या	तीन माह से अधिक अवधि के लंबित वादों की संख्या	आरोपित पदाधिकारी के द्वारा सहयोग नही करने के कारण लंबित वादों की संख्या	उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा सहयोग नही करने के कारण लंबित वादों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17